राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 31 | अंक 11 | नवम्बर 2010 | नई दिल्ली | मूल्य 5 रु. | पृष्ठ 28

शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में भोपाल में हुई छात्र रैली को सम्बोधित करतीं राष्ट्रीय मंत्री कु. अश्विनी परांजपे

शिक्षा के व्यापारीकरण के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन

जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता में अलगाववादियों द्वारा किए गए हमले में घायल परिषद कार्यकर्ता

शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में रोहतक में हुई छात्र पंचायत को सम्बोधित करते हुए श्री श्रीनिवास एवं मंच पर उपस्थित छात्र नेता

बेंगलुरू में राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यालय का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर

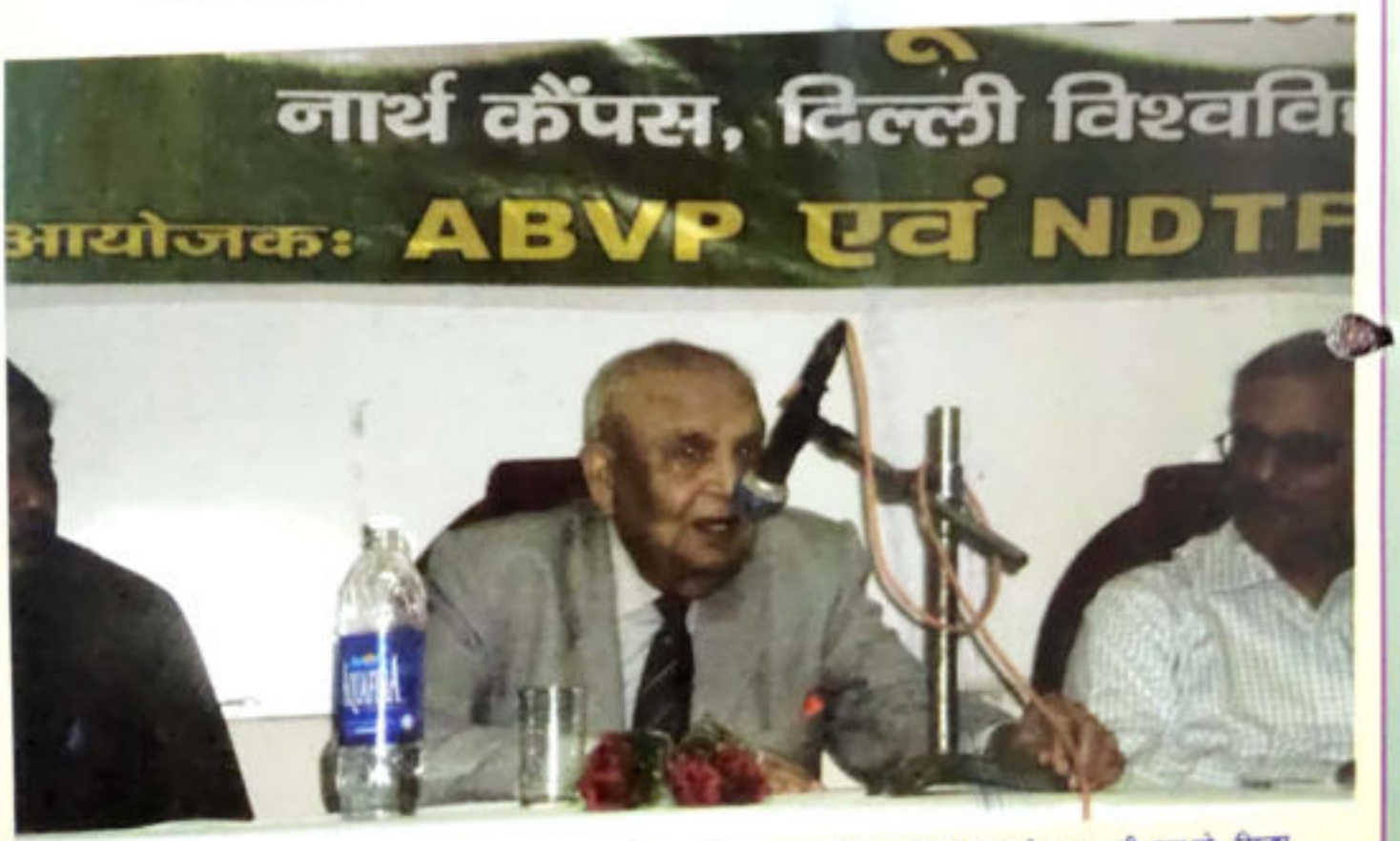

दिल्ली विश्वविद्यालय में कश्मीर विलय दिवस के कार्यक्रम में भाषण करते हुए सेवानिवृत्त ले. जन. श्री एस.के. सिन्हा

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

सम्पादक:
आशुतोष

सम्पादक मण्डल:
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

फोन : 011-43098248
E-mail : chhatrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

मुद्रक और प्रकाशक राजकुमार शर्मा द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट कैम्पस, यूनिवर्सिटी एरिया, दिल्ली-110007 के लिए प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के.30 नवीन शहादरा, दिल्ली. 32 द्वारा मुद्रित

अनुक्रमणिका

विषय	लेखक	पृ.सं.
सम्पादकीय		4
धर्म क्षेत्रे-भारत क्षेत्रे	-जयप्रकाश सिंह	5
शिक्षा के व्यापारीकरण के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन		8
हरियाणा : छात्र महापंचायत		10
शिक्षा पर राजनीतिक फंदे	-जगमोहन सिंह राजपूत	11
उच्च शिक्षा में परिवर्तन	-निरंजन कुमार	13
एक निरर्थक बदलाव	-डॉ. विजय अग्रवाल	15
राजस्थान : प्रांतीय अधिवेशन		16
प. बंगाल : अलगाववादियों का परिषद कार्यकर्ताओं पर खूनी हमला		17
पंजाब : प्रदेश अधिवेशन		18
अलगावाद का जहर	-मिथिलेश झा	19
श्रद्धाञ्जलि : डॉ. जगदीश चन्द्र बसु	-अवनीश सिंह	20
समाचार परिक्रमा		22
दस्तावेज		26

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

शिक्षा के व्यापारीकरण का विषय निरंतर गंभीर होता जा रहा है। विशेष रूप से उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान संप्रग सरकार का शिक्षा के संदर्भ में लिया जाने वाला हर फैसला आम विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर करता नजर आता है। शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा निर्धन विद्यार्थी को बाजार के हवाले करने को तत्पर दिखाई देता है।

भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे शिक्षा प्रशासन के कारण आवश्यक अर्हताएं पूरी न करने वाले निजी संस्थान चांदी काट रहे हैं तो निम्न आय वर्ग के अभिभावकों की संतानों का भविष्य का सपना दिन-प्रतिदिन दूर होता जा रहा है। विश्वविद्यालयों के कुलपति भी जहां कुछ दशक पहले तक जाने-माने शिक्षाशास्त्री होते थे वहीं आज अनेक स्थानों पर नौकरशाह राजनैतिक नियुक्ति पा गय हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जिन लोगों की नियुक्ति की गयी है उनका भी व्यवहार और दृष्टिकोण शिक्षाविद का कम और नौकरशाह अथवा व्यापारी का ज्यादा दिखता है। इसके चलते ही मानविकी के पाठ्यक्रम लगातार कम हो रहे हैं और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की बाढ़ आ गयी है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा के व्यापारीकरण की इस प्रवृत्ति को चुनौती देने का निश्चय किया। गत मई माह में देहरादून में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा प्रभावी आंदोलन खड़ा करने का निर्णय हुआ। परिणामस्वरूप अक्तूबर माह में मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित देश के अनेक प्रांतों में शिक्षा के व्यापारीकरण के विरुद्ध विशाल सम्मेलन व प्रदर्शन आयोजित किये गये। दिसम्बर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में इनकी समीक्षा होगी तथा आगामी चरण की रूपरेखा तय होगी।

सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र अथवा उससे जुड़े विषयों पर प्रा. जगमोहन सिंह राजपूत, निरंजन कुमार तथा डॉ. विजय अग्रवाल के लेख संकलित किये गये हैं। यद्यपि यह लेख पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं किन्तु उनके महत्त्व को देखते हुए इन्हें पत्रिका में स्थान दिया गया है। इसके लिए पत्रिका लेखकों का आभार व्यक्त करती है।

जय प्रकाश सिंह का आलेख 'धर्मक्षेत्रे-भारत क्षेत्रे' वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त प्रासंगिक है जो न केवल परिस्थितियों का व्यापक संदर्भ में विश्लेषण करता है अपितु संघर्ष को वैचारिक धरातल भी प्रदान करता है।

समस्त पाठकों को दीपावली व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

-सम्पादक

धर्म क्षेत्रे-भारत क्षेत्रे

● जयप्रकाश सिंह

गीता का प्रथम श्लोक 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' भारतीय मनीषा को उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति देने वाले ग्रंथ की शुरुआत मात्र नहीं है बल्कि यह व्यवस्था की एक विशेष स्थिति की तरफ संकेत भी करता है। एक ऐसी स्थिति, जब सत्य और असत्य के बीच आमना-सामना अवश्यम्भावी बन जाता है। इस स्थिति में पूरी व्यवस्था व्यापक बदलाव के मुहाने पर खड़ी होती है।

असात्विक शक्तियों की चालबाजियों, फरेबों और तिकड़मों से आम आदमी कराह रहा होता है। अभिव्यक्ति में असत्य हावी हो जाता है। परम्परागत सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक संरचनाओं में सडांध इस कदर बढ़ चुकी होती है अपने हितों के लिए मूल्य एवं आदर्श को ताक पर रखना सहज व्यवहार बन जाता है। राज और समाज को संचालित करने वाली शक्तियां इतनी मदमस्त हो जाती है कि उनके खिलाफ 'लो इन्टेंसिटी वार' अप्रासंगिक हो जाता है।

लेकिन इस स्थिति का सकारात्मक पक्ष भी होता है। वह यह कि सात्विक शक्तियां असात्विक शक्तियों की चुनौती को ताल ठोंककर स्वीकार करती हैं। इस कारण प्रत्यक्ष संघर्ष अपरिहार्य बन जाता है। दोनों पक्षों को एक-दूसरे के खिलाफ शंखनाद करना पड़ता है। चूंकि यह संग्राम धर्म की स्थापना के उद्देश्य से लड़ा जाता है इसलिए जिस भूमि पर सेनाएं डटती हैं, वह धर्मभूमि बन जाती है। इस स्थिति की एक विशेषता यह भी है कि अपने तमाम अच्छे आग्रहों के बावजूद संचार और संचारक (मीडिया और पत्रकार) असात्विक शक्तियों के पाले में ही खड़े दिखाई देते हैं और उनकी भूमिका मात्र आंखों देखा हाल सुनाने तक सीमित हो जाती है।

भारत जिस कालखण्ड से गुजर रहा है उसमें भी भारतीयता और अभारतीयता के बीच का संघर्ष तेजी से 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इस युद्ध का क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक सीमित न रहकर सम्पूर्ण भारत है। एक लम्बी योजना के तहत उन शक्तियों पर निशाना साधा जा रहा है जो वर्तमान प्रणाली में भारतीयता को स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय प्रकृति और तासीर पर आधारित वैकल्पिक व्यवस्था को गढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं।

इस बिन्दु पर भारतीयता और अभारतीयता के बीच के संघर्ष को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। यह संघर्ष दिन, माह और वर्ष की सीमाओं को बहुत पहले ही लांघ चुका है और पिछले कई सौ वर्षों से सतत जारी है। कई निर्णायक दौर आए। कई बार ऐसा लगा कि भारतीयता सदैव के लिए जमींदोज हो गयी है लेकिन अपनी अदम्य धार्मिक जिजीविषा और प्रबल सांस्कृतिक जठराग्नि की बदौलत ऐसे तमाम झंझावातों को पार करने में वह सफल रही। 17वीं सदी तक भारतीयता पर होने वाले आक्रमणों की प्रकृति बर्बर और स्थूल थी। इस दौर के आक्रांताओं में सांस्कृतिक समझ का अभाव था और वे जबरन भारतीयता को अपने ढांचे में ढालने की कोशिश कर रहे थे।

18वीं सदी में आए आक्रांताओं ने धर्म और संस्कृति

में छिपी भारतीयता की मूलशक्ति को पहचाना और उसे नष्ट करने के व्यवस्थागत प्रयास भी शुरू किए। इस दौर में भारतीयता पर दोहरे आक्रमण की परम्परा शुरू हुई। बलपूर्वक भारतीयता को मिटाने के प्रयास यथावत जारी रहे साथ ही भारतीयों में भारतीयता को लेकर पाए जाने वाले गौरवबोध को नष्ट करने का एक नया आयाम आक्रांताओं ने अपनी रणनीति में जोड़ा। 1990 के बाद 'मीडिया-मार्केट गठजोड़' के कारण लोगों में तेजी से रोपी जा रही उपभोक्तावादी जीवनशैली के कारण भारतीयता पर आक्रमण का एक नया तीसरा मोर्चा भी खुल गया।

'मीडिया-मार्केट गठजोड़' का भारतीयता से आमना-सामना अवश्यम्भावी था क्योंकि भारतीयता त्यागपूर्वक उपभोग के जरिए आध्यात्मिक उन्नति के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कहती है जबकि दूसरा पक्ष उपभोग को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानता है और अंधाधुंध उपभोग पर आधारित जीवन-शैली को बढ़ावा देता है। भारतीयता पर आक्रमण करने वाले इस त्रिकोण के अन्तर्सम्बंध आपस में बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। कहीं-कहीं तो वे एक-दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए भी दिखते हैं। लेकिन भारतयीता से इन तीनों को चुनौती मिल रही है। इसलिए इस त्रिकोण ने भारतीयता की समाप्ति को अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम का हिस्सा बना लिया है।

यह त्रिकोण इन्द्रेश के नाम को अजमेर बम विस्फोट से जोड़कर एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। इससे जहां एक तरफ त्रिकोण के सर्वाधिक सशक्त प्रतिरोधी की राष्ट्रवादी और लोककल्याणकारी छवि को धूमिल किया जा सकेगा वहीं इस्लामिक आतंकवाद के समकक्ष हिन्दू आतंकवाद शब्द खड़ा कर हिन्दू-मुस्लिम संवाद के एक संभावित धरातल को नष्ट भी किया जा सकेगा।

इस अभारतीय त्रिकोण के उभार के कारण संघर्ष की प्रकृति और त्वरा में व्यापक बदलाव दिखने लगे हैं। पहले दोनों पक्षों के बीच अनियोजित अथवा अल्पयोजनाबद्ध ढंग से विभिन्न मोर्चों पर छोटी-मोटी लड़ाईयां होती रही हैं। अब सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से भारतीयता पर आक्रमण हो रहे हैं इसलिए अब महासंग्राम का छिड़ना तय सा दिख रहा है।

पिछले 2 वर्षों से हिन्दू आतंकवाद की अवधारणा को रोपने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका जिस तरह से प्रतिवाद हो रहा है, वह भावी महासंग्राम का कारण बन सकता है। हिन्दू आतंकवाद की अवधारणा अभारतीय शक्तियों का एक व्यवस्थित और दूरगामी प्रयास है। पश्चिम में तेजी से फैल रही आध्यात्मिकता तथा उदात्त और समग्र भारतीय जीवनशैली की बढ़ती स्वीकार्यता से भयभीत अनुदार सभ्यताएं इस अवधारणा के जरिए वस्तुतः उपभोक्तावादी जीवनशैली और पूंजीवादी दर्शन के लिए सुरक्षा कवच तैयार करना चाहती हैं।

योग और आयुर्वेद के प्रति सम्पूर्ण दुनिया की नई पीढ़ी का आकर्षण बढ़ रहा है। इसी तरह अनेक संस्थाएं और संत पश्चिम में आध्यात्मिकता की अलख जगा रहे हैं और वहां नई पीढ़ी इस ओर तेजी से आकर्षित हो रही है। इस आकर्षण भाव के चलते भारतीयता विरोधी त्रिकोण के हाथ-पांव फूल गए हैं। भारतीय दर्शन की यह स्वीकार्यता जहां एक और चर्च की वैचारिक जड़ता और अवैज्ञानिकता को रेखांकित करती है वहीं पूंजीवादी दर्शन पर भी कठोर प्रहार करती है।

योग और आयुर्वेद केवल रोग मुक्ति नहीं देते बल्कि जीवन शैली बदलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसके साथ शाकाहार आता है, संयम आता है, सादगी आती है, व्यसनमुक्ति आती है जैसे-जैसे यह सद्गुण बढ़ते हैं, मनुष्य का रोग ही नहीं घटता, भोग की प्रवृत्ति भी घटती है। इसका सीधा असर उपभोक्तावाद पर आधारित पूंजीवाद पर होता है। इसलिए पूंजी और उपभोग पर आधारित जीवनशैली के उपासक योग और आयुर्वेद का गला उसके घर में ही घोंट देना चाहते हैं। इसके लिए वे अपनी आर्थिक-राजनैतिक-सामरिक

शक्तियों का भरपूर उपयोग करते हैं। भारत के सत्ता प्रतिष्ठानों में जमे उनके प्रतिनिधि उनके इस खेल के मोहरे बनते हैं।

भारतीयता की छवि को संकीर्ण और कट्टर पेश कर यह त्रिकोण उसके प्रति तेजी से पनप रहे आकर्षण भाव को भंग करना चाहता है। हिन्दू आतंकवाद का नया शिगूफा छोड़कर इस त्रिकोण ने भारतीयता की ध्वजवाहक शक्तियों को भारत में ही घेरने की रणनीति बनायी है। वे जानते हैं कि जब तक यहां का समाज बिखरा और बंटा रहता है, उन्हें भारत की धरती पर अपना हितसाधन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। संगठित भारतीय समाज उनके लिए चुनौती पेश करता है। इसलिए अगर वे भारत के संसाधनों को निचोड़ना चाहते हैं तो उन्हें पहले भारत की संगठनशक्ति पर चोट करनी होगी। यही कारण है कि देश की राष्ट्रवादी शक्तियां उनके निशाने पर हैं। उनके पिट्ठुओं द्वारा गढ़े गये भगवा आतंकवाद के निराधार जुमले का निहितार्थ यही है। सत्ता और मीडिया से जुड़े कुछ लोगों और समूहों का यह चीत्कार सत्य का संधान नहीं बल्कि सात समुन्दर पार बैठे आकाओं के सामने अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश है।

भारत तेजी से 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कोई ऐसा संजय नहीं दिखाई दे रहा है जो असत्य के पाले में रहते हुए भी अंधी सत्ता को बीच-बीच में टोक कर उसे सत्य मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता रहे और स्थिति की भीषणता की तरफ उसका ध्यान भी आकर्षित करे।

इस पूरे प्रकरण में मीडिया की अतिउत्साही भूमिका भी देखने लायक है। दो वर्ष पहले तक किसी पंथ को आतंकवाद से न जोड़ने का उपदेश देने वाला मीडिया बिना किसी सबूत और साक्ष्य के हिन्दू आतंकवाद शब्द को बार-बार दोहरा रहा है। मजेदार तथ्य यह है कि हिन्दू आतंकवाद शब्द को मीडिया के जरिए आम-लोगों से परिचित पहले करवाया गया और उसकी पुष्टि के सबूत बाद में जुटाए जा रहे हैं। एक अवधारणा के रूप में हिन्दू आतंकवाद हाल के दिनों में मीडिया ट्रायल का सबसे बड़ा उदाहरण है।

सबसे पहले मालेगांव प्रकरण में हिन्दू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकरण में सांगठनिक स्तर पर अभिनव भारत तथा व्यक्तिगत स्तर पर साध्वी प्रज्ञा का नाम उछाला गया। मालेगांव विस्फोट प्रकरण में मीडिया को तमाम मनगढंत कहानियां उपलब्ध कराने के अतिरिक्त आजतक जांच एजेंसियां कोई ठोस सबूत नहीं इकट्ठा कर पायी हैं। अभिनव भारत जैसे अनजान संगठन को लपेटने पर भी भारतीयता पर कोई आंच आती न देख अब इस त्रिकोण ने भारत और विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिन्दू आतंकवाद से जोड़ने का कुत्सित प्रयास शुरु कर दिया है। संघ इस त्रिकोण के निशाने पर पहले भी सबसे ऊपर रहा है। क्योंकि आतंकवाद, धर्मान्तरण और खुली अर्थव्यवस्था की विसंगतियों के प्रति संघ आमजन को जागरुक करता रहा है। इस कारण पूरे भारत में धीरे-धीरे इस त्रिकोण के खिलाफ एक प्रतिरोधात्मक शक्ति खड़ी होती जा रही थी।

अब इन शक्तियों ने संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक इन्द्रेश, जिन्हें मुसलमानों को भी संघ के कार्य से जोड़ने के लिए विशेष रुप से जाना जाता है, का नाम अजमेर बम विस्फोट में घसीटा है। यह त्रिकोण इन्द्रेश के नाम को अजमेर बम विस्फोट से जोड़कर एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। इससे जहां एक तरफ त्रिकोण के सर्वाधिक सशक्त प्रतिरोधी की राष्ट्रवादी और लोककल्याणकारी छवि को धूमिल किया जा सकेगा वहीं इस्लामिक आतंकवाद के समकक्ष हिन्दू आतंकवाद शब्द खड़ा कर हिन्दू-मुस्लिम संवाद के एक संभावित धरातल को नष्ट भी किया जा सकेगा।

भारत तेजी से 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कोई ऐसा संजय नहीं दिखाई दे रहा है जो असत्य के पाले में रहते हुए भी अंधी सत्ता को बीच-बीच में टोक कर उसे सत्य मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता रहे और स्थिति की भीषणता की तरफ उसका ध्यान भी आकर्षित करे। ■

शिक्षा के व्यापारीकरण के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन

भोपाल में विशाल छात्र रैली सम्पन्न

भोपाल । राजधानी में शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा बढ़ती फीस के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने छात्रों की रैली निकाली और आमसभा का आयोजन किया। सभा में प्रदेश के कोने-कोने से आए 35 हजार से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए।

सुबह 11.00 बजे से एक्सीलेंस स्कूल, ओल्ड बेनजीर ग्राउंड तथा शाहजहानी पार्क से छात्रों की विराट रैलियां निकाली गई। तीनों रैलियां दोपहर 2.00 बजे न्यू मार्केट, दशहरा मैदान में आयोजित सभा में समाहित हो गईं। अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा, सह संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश मंत्री भारती कुम्भारे, राष्ट्रीय मंत्री अश्विनी परांजपे, दिल्ली विवि के छात्र संघ अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी तथा राजस्थान विवि के छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव ने सभा को संबोधित किया।

शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में आर-पार की लड़ाई का संकल्प लेते हुए अभाविप के पदाधिकारी एवं छात्र नेता

बैतूल। शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर शहर के स्कूल और कालेजों में छात्रों ने अपनी अनुपस्थिति से शिक्षा के व्यवसायीकरण का पुरजोर विरोध जताया। अभाविप शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन कर रही है।

अभाविप का बंद पूर्णत: सफल रहा। बंद के दौरान छात्रों ने जेएच कॉलेज एवं कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। एसडीएम संजीव श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करने की मांग की गयी।

अभाविप के सुनील पवार ने बताया कि आज व्यावसायिक शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि यह आम आदमी की पहुंच से बाहर है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए लाखों रुपए फीस ली जा रही है। राकेश दौड़के ने बताया कि पैसों के बल पर फर्जी डिग्री बनाई जा रही है। पैसों के दम पर ही प्रवेश भी हो रहे हैं। इससे प्रतिभावान गरीब छात्र को मौका नहीं मिल रहा है। विभिन्न प्रकार के मदों से पैसा लेकर छात्रों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ■

देहरादून। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिक्षा के व्यापारीकरण पर डीएवी स्नातकोत्तर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित एक सभा में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष रमाकांत श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार देश में फैल रहे शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है।

उन्होंने कहा कि देशभर में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में लगातार हो रही शुल्क वृद्धि के कारण गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और करियर के नाम पर छात्रों को छला जा रहा है। रोज़गार पाने की लालसा के चलते छात्र इन संस्थानों को प्रतिवर्ष लाखों रूपये देने को मजबूर हैं।

शिक्षा के व्यावसायीकरण के विरोध में परिषद की आगामी गतिविधियों की जानकारी देते हुए श्री रमाकांत श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य के सभी कॉलेजों में आगामी 15 नवम्बर को प्रदर्शन किया जाएगा, और फिर 29 नवम्बर को जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इसी क्रम में 6 दिसम्बर को विद्यार्थी परिषद जिला न्यायाधीश, राज्य के शिक्षा मंत्री और सांसदों को अपनी प्रमुख मांगों का एक ज्ञापन सौंपेगा।

■

चंडीगढ़। देश के विश्वविद्यालयों में आए दिन बढ़ रही फीस को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने पंजाब विश्वविद्यालय में भी 9 नवम्बर को अपना विरोध प्रदर्शन किया।

अभाविप के नेता दिनेश चौहान ने कहा- जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में किसी न किसी बहाने से फीस बढ़ाई जा रही है उसी का परिणाम है कि शिक्षा व्यावसायीकरण की ओर जा पहुंची है।

उन्होंने कहा कि परिषद ने कालेजों सहित स्कूलों की फीस संरचना पर सभी राज्यों में एक सर्वेक्षण आयोजित किया था जिसमें पाया गया कि वर्तमान में जिस तरह से फीस का मौजूदा स्वरूप है उसके चलते शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुकी है।

चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालयों में फीस की संरचना ऐसी होनी चाहिए जो समाज के हर तबके के दायरे में आती हो। इसमें सुधार के लिए हम बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन करेंगे।

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सूचना के अधिकार के तहत पंजाब विश्वविद्यालय के प्रशासन से जब कभी कोई जानकारी मांगी गई वह प्राय उपलब्ध नहीं कराई गई है। परिषद इसके लिए भी अपनी आवाज बुलंद करेगी। ■

सब से अधिक आनंद इस भावना में है कि हमने मानवता की प्रगति में कुछ योगदान दिया है। भले ही वह कितना कम, यहां तक कि बिल्कुल ही तुच्छ क्यों न हो? -डा. राधाकृष्णन

शिक्षा का व्यापारीकरण रोकने के लिए अभाविप की हरियाणा सरकार को चेतावनी

छात्र महापंचायत में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर का पगड़ी पहनाकर सम्मान करते हुए कार्यकर्ता

रोहतक। गत 26 अक्तूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के आह्वान पर प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदेश भर के सभी जिलों से हजारों छात्र महम चौबीसी पर पहुंचे। महापंचायत में छात्रों ने शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने के लिए सरकार को 26 दिसम्बर तक का अल्टीमेटम दिया। छात्र नेताओं ने कहा कि यदि निर्धारित समय तक उनकी मांगे नहीं मानी गयीं तो 26 दिसम्बर से पूरे प्रदेश में छात्र सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ेगा।

इस मौके पर अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि हरियाणा में प्रदेश सरकार ही नहीं केन्द्र सरकार में भी कपिल सिब्बल जैसे व्यक्ति शिक्षा की दुकानों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि हरियाणा की संस्कृति की प्रतीक पंचायत का निर्णय समाज का निर्णय होता है। इसलिए इस निर्णय को समाज में लागू किया जाना चाहिए। अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री व प्रांत संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि हरियाणा सरकार सत्ता के मद में अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे बैठी है। उसे हरियाणा के छात्रों के हितों से कुछ लेना-देना नहीं है।

छात्र संघ चुनाव पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए प्रदेश मंत्री विक्रम कोका ने कहा कि पिछले 14 सालों से हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बंद है। लेकिन इसके बावजूद आज भी छात्रसंघ चुनाव के मद में छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है। यह राशि बढ़कर 21 करोड़ तक जा पहुंची है। अभाविप ने सरकार से इसकी जांच की मांग की है।

महापंचायत को प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, जोगेन्द्र बल्हारा, प्रदेश सहमंत्री शेखावत, सुभाष कलसाना, राजकुमार शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप पूनिया और संजय लकड़ा ने सम्बोधित किया। महापंचायत में छात्रों ने प्रदेश सरकार को 26 दिसम्बर तक मांग पर विचार करने का समय दिया। यदि इस निर्धारित समय में सरकार ने मांगे नहीं मानी तो छात्र सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेगा। यह निर्णय छात्रों ने अपने दोनों हाथ उठाकर संकल्प लेते हुए लिया। महापंचायत में 21 जिलों के 119 स्थानों, 8 विश्वविद्यालय, 192 कालेजों से 10513 छात्रों ने सहभागिता की।

■

शिक्षा पर राजनीतिक फंदे

● जगमोहन सिंह राजपूत

जनतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र शासन पद्धति के लिए वह सर्वश्रेष्ठ विधा है जो आज तक की सोच में विशालतम स्वीकार्यता के साथ उभरी है। लगभग प्रत्येक देश अपने को रिपब्लिक, डेमोक्रेसी जैसे शब्दों से आभूषित करता है। माओ का चीन तथा स्टालिन का सोवियत संघ भी अपने को रिपब्लिक ही घोषित करते रहे। पाकिस्तान भी इस्लामिक रिपब्लिक है। अमेरिका इस समय सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है। यानी इन सभी देशों में सार्वभौम है जनता।

विद्वान इतिहासकार, राजनीति शास्त्र के पंडित हमें उदाहरण देकर समझाते रहते हैं कि तानाशाही या किसी प्रकार के कुछ गिने-चुने प्रभावशाली, धनवान, चतुर लोगों के शासन से कहीं बेहतर है जनता का अपना शासन, उसकी भागीदारी और सार्वभौमिकता का उसमें निहित होना। यह सब कितना कुछ आकर्षक लगता है। यही विद्वान हमें यह भी सिखाते हैं कि जब वर्ग विशेष का प्रभावशाली गुट यानी सामान्यत: एलीट या अभिजात्य वर्ग सत्ता पर काबिज हो जाता है तब उसका पहला उद्देश्य तथा लक्ष्य अपने सम्पूर्ण स्वरूप में उसके सामने उभरता है। सत्ता को अपने पास बनाए रखना, उसके लिए हर प्रकार के साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग एवं प्रयोग करने में न हिचकना।

इस प्रक्रिया में स्वाभाविक है बहुसंख्यक जनता के अधिकारों का हनन होता है, अन्याय होता है। यह सतत लगने वाली प्रक्रिया भी टूटती है जब सामान्यजन की जानकारी बढ़ती है तथा उन्हीं में से कुछ लोग साहस करते हैं, आगे आते हैं। यह प्रक्रिया अत्यन्त जटिल तथा कांटों भरी होती है। इसी में कभी महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे युग नायक उभरते हैं तो कभी माओ, स्टालिन जैसे लोग भी सामने आते हैं। जब सारा विश्व 21वीं सदी में प्रवेश की तैयारी कर रहा था, उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका था तब अफगानिस्तान में शासक तालिबान शिक्षा संस्थाओं को नष्ट कर रहे थे, लड़कियों का पढ़ना-लिखना, घर के बाहर निकलना तथा पुरुषों के साथ कार्य करना रोक रहे थे। हत्या, विस्फोट, पाषाण कालीन सजाएं-सभी कुछ निर्बाध गति से वहां चला। अमेरिका ने आक्रमण किया। तालिबान सत्ता से हटे, मगर जो विनाश वह कर चुके थे उसकी पूर्ति कर पाना आसान नहीं है। इराक में भी स्थिति यही बनी। विश्व के अनेक देशों में लगभग ऐसी ही स्थिति है। वहां बच्चों, माताओं, गरीबी, भुखमरी जैसे पक्ष राजनीति तथा राजनीतिज्ञों के स्वार्थ में दब जाते हैं।

यहां पर एक बार यह याद करना उचित होगा कि 1990 में विश्व के 176 राष्ट्रों ने सभी को शिक्षा देने का फैसला किया था। 2000 में डकार-सेनेगल में समग्र रूप से सबको शिक्षा, भुखमरी तथा गरीबी तथा अन्य सम्बंधित पक्षों पर लगभग 200 राष्ट्रों ने 2015 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य स्वीकार किए। इसके बावजूद आज भी शिक्षा का अधिकार विश्व में अनेक स्थानों पर राजनीतिक स्वार्थों की बलि चढ़ रहा है। आज के युग में किसी बच्चे को शिक्षा से दूर रखना देशद्रोह से भी बड़ा अपराध माना जाना चाहिए।

आज देश में शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम के लागू होने के वर्ष में सभी चाहते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। ऐसे में जम्मू-कश्मीर से यह खबरें आती हैं कि नेताओं ने अपील जारी की है कि सरकार भले ही स्कूल खुले रखने के प्रबंध करे, बच्चे स्कूल न भेजे जाएं। क्या 21वीं सदी में कोई व्यक्ति, समूह, वर्ग या संप्रदाय इस सोच के साथ भविष्य के उज्ज्वल सपने देख सकता है? शिक्षा तथा बच्चों के प्रति संवेदनहीनता का यह एक बहुत ही भयावह उदाहरण है। लगभग 20 वर्षों से जम्मू-कश्मीर के बच्चे और युवा वहां की राजनीतिक उठापटक के कारण अपना बचपन तथा भविष्य के

अवसर खो रहे हैं, अनेक बंधनों और गोलियों तथा ग्रेनेड्स के शोर के बीच बड़े हो रहे हैं।

तीन महीने किसी बच्चे को या किसी को भी कर्फ्यू में बंद रहना पड़े तो उसके मानवीय अधिकारों का इससे बड़ा हनन क्या हो सकता है? इधर धीरे-धीरे यह जानकारियां सामने आई हैं कि लगभग वे सब परिवार जो साधन सम्पन्न है, जनजीवन में नेता कहलाते है, आंदोलन करते हैं, स्कूल नहीं खुलने देते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में या अन्य प्रांतों के नामी-गिरामी स्कूलों में शिक्षा दिला रहे हैं। वे लोग जो अलगाववादियों के साथ खड़े होने, उनसे बात करने के पक्षधर रहे हैं, इस पक्ष पर चुप क्यों हैं?

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

हल्द्वानी में प्रतिभा सम्मान समारोह सम्पन्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हल्द्वानी नगर इकाई द्वारा एम.बी.पी.जी. कालेज में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें हल्द्वानी नगर के 40 विद्यालयों से 123 छात्राओं को सम्मानित किया गया।

सम्मान समारोह का उद्घाटन प्रदेश के परिवहन व सहकारिता मंत्री श्री बंसीधर भगत, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डा. विनय कुमार पाठक, विद्यार्थी परिषद् के प्रदेश मंत्री ब्रिजेश बनकोटी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए अभाविप के प्रदेश मंत्री ब्रिजेश बनकोटी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् अपने रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को देश व समाज से जोड़ने का कार्य कर रही है। देश भर में अभाविप के 18 लाख से अधिक सदस्य हैं, देश की सुरक्षा का प्रश्न हो या देश में प्राकृतिक आपदा का समय हो, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सबसे आगे रहकर अग्रिम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रसंघों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद् छात्रों में सफल नेतृत्व भी विकसित कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री बंसीधर भगत ने कहा कि छात्रों को विवेकानन्द के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज देश को सकारात्मक सोच वाले युवा की आवश्यकता है। अभाविप देश की इस आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अक्ल एवं उम्र की भेंट जब होती है तो बहुत बड़े-बड़े लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं। अत: युवाओं को समय के साथ-साथ चलकर आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डा. विनय कुमार पाठक, कार्यक्रम अध्यक्ष कर्नल दर्शन सिंह कार्की, प्राचार्य डा. बी.एस.बिष्ट, डा. अनिल कपूर आदि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए। ■

कश्मीर विलय दिवस कार्यक्रम उधमपुर में सम्पन्न

उधमपुर। राज्य के भारत में विलय दिवस के अवसर पर अभाविप ने शहीद भगत सिंह पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया। परिषद नेता मान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मोमबत्ती जलाकर विलय दिवस हर साल धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। ■

उच्च शिक्षा में परिवर्तन

● निरंजन कुमार

पिछले दिनों देश के करीब 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक में उच्च शिक्षा के सम्बंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोतर स्तर प्रवेश के लिए एक अभियोग्यता परीक्षा कराई जाए। इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति बीबी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति भी बना दी गई है जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।

प्रस्ताव के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बीए, बीएससी और बीकॉम आदि स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए एक संयुक्त परीक्षा कराई जाएगी। आरंभ में तो प्रस्ताव था कि सिर्फ इस अभियोग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट से उम्मीदवारों को अपनी वरीयता के आधार पर विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए।

हालांकि यह अच्छा हुआ कि इसी बैठक में केवल इस परीक्षा के अंकों के आधार पर ही प्रवेश को नकार दिया गया। यह निर्णय लिया गया है कि इन अंकों के अतिरिक्त बारहवीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों को भी एडमिशन का आधार बनाया जाए। अर्थात् दोनों के अंकों जो जोड़कर योग्यता सूची बनाई जाएगी। बारहवीं के अंकों को सिरे से खारिज कर देना एक तरह से उस सारे ज्ञान और मेहनत पर पानी फेर देना होता, जो विद्यार्थियों ने अब तक हासिल किया था।

संयुक्त अभिरुचि परीक्षा का जो प्रस्तावित प्रारूप है, वह भी थोड़ा शहरी और कान्वेंट स्कूलों की ओर झुका सा है, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों-कस्बों के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कठिनाई होगी। परीक्षा के प्रारूप में सामान्य ज्ञान और व्यक्तित्व परीक्षण विषयों से संबंधित सवाल पूछे जाने का प्रस्ताव था। जाहिर है कि इन विषयों में गांवों-कस्बों के अति प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि न तो उन स्कूलों में पर्याप्त संसाधन, आधुनिक आधारभूत संरचनाएं और व्यवस्था होती है और न ही उपरोक्त विषय में उनका वैसा शिक्षण-प्रशिक्षण होता है। अत: यह पैटर्न तो उनके विरुद्ध ही जाएगा। दरअसल, इस तरह की अभिरुचि और अभियोग्यता परीक्षा की अवधारणा अमेरिका के स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट (सैट) पर आधारित है।

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रवेश सैट स्कोर के आधार पर किया जाता है। वैसे वहां भी कुछ विश्वविद्यालयों ने सिर्फ सैट के आधार पर एडमिशन का विरोध किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कुलपति रिचर्ड एटकंसन ने 2001 में सैट पर बहुत ज्यादा जोर देने का विरोध किया था। हालांकि सैट का परीक्षण पैटर्न काफी संतुलित है। इसमें गणित, विवेचनात्मक पठन और लेखन पर सवाल होते हैं, जिनमें सिर्फ कान्वेंट स्कूलों का वर्चस्व नहीं होता। फिर वहां सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हमारे यहां जैसा कोई ज्यादा अंतर भी नहीं होता। आशा है कि इस परीक्षा का प्रारूप बनाते वक्त देश के ग्रामीण और कस्बाई स्कूलों की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा।

इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है बारहवीं के अंकों का। यहां मेरा प्रस्ताव है कि बारहवीं के अंकों में भी एक स्केलिंग या समायोजन किया जाए। होता यह है कि सीबीएसई बोर्ड अथवा आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में 90 फीसदी अंक लाना अत्यन्त कठिन नहीं है। हजारों छात्र इससे अधिक अंक ले आते हैं। जबकि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि अन्य बोर्डों में 85 प्रतिशत अंक तो टॉपर भी यदाकदा ही ला पाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि विभिन्न बोर्ड परीक्षा प्रणालियों में समानता हो, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भेदभाव का शिकार न होना पड़े। इस बैठक का एक महत्वपूर्ण बिंदु था-क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था पर रजामंदी। यह अपने-आप में

एक क्रांतिकारी व्यवस्था है, जिसमें कोई प्रतिभाशाली छात्र उन विषयों की पढ़ाई दूसरे विश्वविद्यालयों में कर सकता है, जिनकी पढ़ाई उसके विश्वविद्यालय में नहीं होती और वहां प्राप्त क्रेडिट या अंक उसके कुल अंकों में जुड़ जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में यह व्यवस्था बहुत पहले से है। इन देशों में तो न केवल एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में क्रेडिट ट्रांसफर होता है, बल्कि एक देश से दूसरे देश के विश्वविद्यालय में भी यह सम्भव है। कुछ ऐसी ही स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश में भी सम्भव है, जिसमें हमारे छात्र बाहर और विदेशी छात्र हमारे यहां शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इससे हमारे छात्रों को जहां श्रेष्ठ विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिल सकेगा, वहीं विदेशी छात्रों के आगमन से हमें विदेशी मुद्रा तो मिलेगी ही, साथ ही हमारा सॉफ्ट पावर भी इसमें बढ़ेगा।

लेकिन इस प्रस्ताव में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि यह प्रावधान सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए है। राज्य-विश्वविद्यालय इससे बाहर होंगे। यह सच है कि हमारे कॉलेज और राज्यस्तरीय विश्वविद्यालय उत्कृष्ट कोटि के नहीं हैं, लेकिन इसका कारण वहां प्रतिभा की कमी न होकर धन की कमी, राजनीति और प्रशासनिक अकुशलता है, जिसे दृढ़ इच्छाशक्ति से ही दूर किया जा सकता है। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि बीए-बीएड और बीएससी-बीएड का चार साल का एकीकृत कोर्स भी शुरू किया जाएगा। दरअसल भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की बात काफी समय से चल रही है, खासतौर पर उच्च शिक्षा में।

मानव संसाधन मंत्री ने इस दिशा में कई कदम भी उठाए हैं, जिसमें कुछ तो महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, लेकिन कुछ कदम ऐसे भी हैं जो लगता है कि हड़बड़ी में और बिना ठीक से सोचे-विचारे उठा लिए गए हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण वजह है कि ये बहसें सिर्फ अंग्रेजीदां लोगों के बीच और अंग्रेजी मीडिा तक सिमट कर रह जाती हैं जो दुर्भाग्य से इस देश की जमीनी हकीकत से कम ही वाकिफ हैं। अंग्रेजीदां नीति नियामक हिंदीभाषी जनता को नजरअंदाज किए रहते हैं। कई सुधारात्मक कदम तो ऐसे हैं जो अमेरिकी या पश्चिमी यूरोप के देशों की तर्ज पर लिए गए हैं। यह तो ठीक है कि ये देश दुनिया के सर्वाधिक विकसित देश होने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सिरमौर हैं। उनसे हम सबक तो ले सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियां और नियम उनके अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए हैं। अत: यह जरूरी है कि पाश्चात्य देशों के अंधानुकरण की जगह हम अपनी शिक्षा नीति, अपनी जरूरतों और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाएं।

(लेखक दिल्ली विवि में एसोसिएट प्रोफेसर हैं)

साभार : दैनिक जागरण

अरुणाचल प्रदेश

दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन

इटानगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सामाजिक संस्था सेवा भारती के साथ मिलकर दो दिवसीय दंत चिकित्सा एवं रक्तगट जांच शिविर का आयोजन किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बयाबंग राणा ने अभाविप द्वारा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में इस प्रकार के किए जा रहे रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के आयोजन में प्रमुख सहयोगी रही डा. प्रतिभा अठावले का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि 56 वर्ष की आयु में भी राज्य के वनवासियों के उत्थान के लिए बीते दस वर्षों से निडर होकर कार्य कर रही डा. प्रतिभा अठावले युवाओं के लिये प्रेरणादायक है।

इस मौके पर कॉलेज के उपाध्यक्ष टी. टमुक ने कहा कि डा. अठावले द्वारा किये जा रहे सामाजिक कार्यों से निश्चित ही छात्रों एवं इससे जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर अभाविप के राज्य सचिव जयंत सेकिया ने अभाविप द्वारा किए जा रहे रचनात्मक, संगठनात्मक कार्यों एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। ■

एक निरर्थक बदलाव

सिविल परीक्षा के नए पैटर्न पर डॉ. विजय अग्रवाल की राय

प्रशासन में सुधार लाने की राष्ट्रीय चिंता को दूर करने के लिहाज से भारत सरकार ने हाल ही में अगले साल होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण में एक बदलाव किया है। बदलाव यह है कि पहले जहां परीक्षार्थी को जनरल नॉलेज के अनिवार्य विषय के साथ एक वैकल्पिक विषय लेना होता था वहीं अब वैकल्पिक विषय के स्थान पर सभी के लिए समान पेपर कर दिया गया है। और इसे नाम दिया गया है-एप्टीट्यूट टेस्ट।

यह पेपर प्रशासन में कितना सुधार कर सकेगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस नए पेपर को लेकर यह संदेह उभरता है कि यह हमें फिर से कहीं न कहीं 1979 के पहले की उस स्थिति में ले जाने का षड्यंत्र दिखाई देता है जब इस परीक्षा का माध्यम इंग्लिश करके इस सर्वोच्च सेवा को मात्र दो प्रतिशत लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। लागू किए गए इस नए पेपर में सात बिंदुओं में से एक बिंदु है-इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंसन स्किल्स (दसवीं के स्तर का)। इस पेपर में लगभग 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी आब्जेक्टिव टाइप के होंगे।

यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि इंग्लिश भाषा पर बीस प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिस परीक्षा में प्रतिवर्ष औसतन तीन लाख परीक्षार्थी बैठते हों, जिनमें से लगभग बारह हजार का चयन होता हो और जहां एक-एक नम्बर का अंतर आपके भाग्य का फैसला करत हो, जाहिर है कि यदि आप किसी अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल के विद्यार्थी नहीं रहे हैं तो आपकी यहां खूबसूरत वैधानिक तरीके से छंटनी हो जाएगी। हालांकि कहा तो यही जाता है कि यह केवल दसवीं कक्षा के स्तर का ही तो है और किसी भी पढ़े-लिखे आदमी को इतनी अंग्रेजी तो आती ही है, लेकिन ऐसा कहने वाले ये वे लोग हैं जिनकी यात्राएं राजधानी से राजधानी की ही होती रही हैं। यह छद्म और थोथा तर्क है। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सचमुच में भारतीय प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी काल माना जाना चाहिए, जब उन्होंने कोठारी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सिविल सेवा के दरवाजे प्रत्येक भारतीय भाषा के लिए खोल दिए थे।

पिछले तीस साल की यह यात्रा इस बात की गवाह है कि भारतीय प्रशासन के उच्च स्तर के स्वरूप ने अपने विलायती चोले को उतारकर देसी बाना धारण किया है। अब लगभग आधे सफल युवा उन गांवों के होते हैं जिन्हें अभी भी इस बात का भूत सताता रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि मुख्य परीक्षा में जनरल इंग्लिश के प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण ही न कर पाएं। मुख्य परीक्षा में इसमें पास होना अनिवार्य होता है। प्रशासनिक गलियारों में मैंने कई शहरी अफसरों को अंग्रेजी में यह बड़बड़ाते हुआ सुना है कि इन रीजनल लैंग्वेज वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल का मटियामेट कर दिया है। सरकार को एक आयोग का गठन करना चाहिए ताकि पता चले कि जिन्हें वह सर्वोत्तम सिविल सर्वेंट पुरस्कार से नवाजती है उनकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या आयोग को यह काम भी सौंपा जा सकता है कि विकास और 'गुड गवर्नेंस' के संदर्भ में अंग्रेजी ज्ञान की अनिवार्यता की भूमिका कितनी है।

सवाल है क्या भारतीय भाषाओं के ज्ञान के अभाव में भारत की स्थितियों को सही-सही समझा जा सकता है और क्या स्थितियों को सही-सही समझे बिना केवल अंग्रेजी की जानकारी के दम पर 'गुड गवर्नेंस' किया जा सकता है? फिर यह भी तो है कि यदि अंग्रेजी इतनी ही ज्यादा जरूरी है तो सेलेक्शन के बाद उन्हें अंग्रेजी सिखा दी जानी चाहिए। जब हम भारतीय विदेश सेवा के अफसरों को सेलेक्शन के बाद दूसरे देशों की भाषा सिखा सकते हैं तो क्या राष्ट्रीय भाषाओं के जानकार युवा को चयन के बाद अंग्रेजी नहीं सिखायी जा सकती?

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

राजस्थान

तीन दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन सम्पन्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तीन दिवसीय 46वां प्रांतीय अधिवेशन 24 अक्टूबर 2010 को सम्पन्न हुआ। श्री गंगानगर के अरोड़वंश पब्लिक विद्यालय में आयोजित अधिवेशन में 37 जिलों के 577 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

खुला अधिवेशन में अभाविप रैली को सम्बोधित करते वक्ता एवं मंचस्थ छात्र नेता

अधिवेशन के अलग-अलग सत्रों के दौरान 'ध्येय के अनुरूप जीवन' विषय पर अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सुनील बंसल तथा शिक्षा के व्यापारीकरण विषय पर परिषद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. नागेश ठाकुर का उद्बोधन हुआ। 'राज्य की वर्तमान शैक्षिक स्थिति' एवं 'राज्य की वर्तमान स्थिति' पर दो प्रस्ताव पारित किये गये।

अधिवेशन के आखिरी दिन खुला अधिवेशन किया गया। जिसमें विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर भव्य शोभायात्रा निकाली गयी। अंबेडकर चौराहे पर आयोजित खुले अधिवेशन में कश्मीर समस्या, छात्र संघ चुनाव और शिक्षा के व्यापारीकरण जैसे विषयों पर छात्र नेताओं ने अपना विचार लोगों के सामने रखा।

अधिवेशन में निर्वाचन अधिकारी डा. राजीव सक्सेना ने नये प्रांत अध्यक्ष के रूप में श्री सुनील चतुर्वेदी और प्रांत मंत्री के लिये सोहन आंजना को निर्वाचित किया। इसके बाद नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष श्री सुनील चतुर्वेदी ने प्रांत कार्यकारिणी की घोषणा की। अधिवेशन में कुल 471 छात्र, 67 छात्रायें, 34 प्राध्यापक एवं 5 अन्य कार्यकर्ताओं सहित कुल 577 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में श्री जगदंबा अंध विद्यालय के संचालक स्वामी ब्रह्मदेव जी महराज का आशिर्वचन लोगों को सुनने को मिला। ■

अधिवेशन में उपस्थिति छात्र प्रतिनिधि

अलगाववादियों का परिषद कार्यकर्ताओं पर खूनी हमला

हमले में घायल विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता

माओवादी छात्र संगठन यूनाइटेड स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएसएफ) द्वारा प. बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में कश्मीर की स्वायत्तता के संदर्भ में आयोजित 'आजादी' विषयक संगोष्ठी में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब वक्ताओं में से एक सिद्धार्थ गुहा रॉय ने कश्मीर को भारत से अलग कर देने की वकालत की और अपनी बात के समर्थन में गढ़े गए अधूरे तर्क दिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में संसद हमले के आरोपी रहे एस.ए.आर. गिलानी भी मंच पर उपस्थित थे।

इस पर अरुण शॉ नाम के एक विद्यार्थी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा कश्मीर के शेष भारत के साथ एकीकरण के प्रयास से संबंधित सवाल उठाया। इससे उत्तेजित अलगाववाद समर्थक यूडीएसएफ कार्यकर्ताओं ने छात्र पर हमला बोल दिया।

जब छात्र के बचाव में उतरे अभाविप कार्यकर्ताओं ने संगोष्ठी के बीच में नारेबाजी कर विरोध जताया तो इस पर वहां बैठे माओवादी छात्र संगठन के कार्यकर्ता बिगड़ गए और उन्होंने अरुण शॉ समेत अभाविप कार्यकर्ताओं पर रॉड और लाठियां भांज दी। इस बीच कई कार्यकर्ता घायल हो गए जिनमें से दो कार्यकर्ता नीरज कुमार और याग्निक अग्रवाल को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके अतिरिक्त अमिताब रॉय, गौतम चौधरी और कुमारी तनुश्री रॉय सहित अनेक परिषद कार्यकर्ता घायल हुए।

बताया जा रहा है कि इस आयोजन को लेकर विद्यार्थियों में पहले से ही रोष व्याप्त था कि क्योंकि आयोजको ने समूचे विश्वविद्यालय परिसर को झण्डे-बैनरों से पाट दिया था जिन पर 'कश्मीर हमारा नहीं है' और 'भारतीय सेना बलात्कारियों की सेना' आदि नारे लिखे गए थे। इसको देखते हुए आयोजकों एवं अलगाववाद समर्थित छात्रों द्वारा लोहे की रॉड, लाठी आदि हथियार सभागार में पहले से ही जमा किए गए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसा उत्पात मचाना पूर्व नियोजित था।

अभाविप कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के सामने मुख्य मार्ग पर निर्दोष छात्रों पर हुए हमले और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि विरोध में आम नागरिकों ने भी अपना समर्थन दिया। इसके बाद जादवपुर पुलिस थाने में घटना के विरोध में अभाविप कार्यकर्ताओं ने प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस से इस गोष्ठी के आयोजनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। विदित हो कि इससे पहले ऐसे ही राष्ट्रविरोधी सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में भी हुआ था। उक्त सम्मेलन में भी अलगाववादी नेता एस.आर. गिलानी ही मुख्य वक्ता थे जिसका अभाविप और अन्य संगठनों ने विरोध किया था। ■

जादवपुर विवि में अलगाववादी नेता और संसद हमले के आरोपी रहे एस.आर. गिलानी का विरोध कर रहे परिषद कार्यकर्ता पर हमला करते अलगाववादी

पंजाब प्रांत का अधिवेशन पटियाला में संपन्न

राष्ट्रीय मंत्री श्री श्रीरंग कुलकर्णी को स्मृति चिह्न प्रदान करते हुए पंजाब प्रदेश अध्यक्ष श्री विपिन सेठिया

वर्तमान समय में शिक्षा एक सेवा न होकर व्यापार की वस्तु हो गयी है और शिक्षा के व्यापारीकरण के कारण गरीब व मेधावी छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे है। उक्त बातें अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री श्रीरंग कुलकर्णी ने पंजाब प्रांत के अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये कहीं। उन्होंने मांग की कि सरकार शिक्षा में हो रहे इस व्यापारीकरण को रोकने हेतु शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण तथा उनके संचालन के संदर्भ में केन्द्रीय कानून बनाये।

शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट के लिये राज्य सरकार की नीतियों को मुख्य जिम्मेदार मानते हुए राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मंहगी शिक्षा और व्यापारीकरण के खिलाफ अभाविप सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद शिक्षा में समानता और एकरूपता लाने के लिये हमेशा से मांग करती आ रही है। अभाविप की मांग रही है कि सरकारी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को बन्द किया जाये, शुल्क संरचना का निर्धारण करते समय मात्र आवर्तक व्यय का ही विचार किया जाये न कि संस्थान की स्थापना के पूंजीगत व्यय का। उच्च शिक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राज्य स्तरीय एकल प्रवेश परीक्षा शुरू की जाये, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में अन्य पदों पर छात्रों से वसूली जा रही फीस को रोका जाये तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सीट आवंटन तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण किया जाये।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब प्रांत का प्रांतीय अधिवेशन प्रेम धाम सर्वहितकारी स्कूल, पटियाला में संपन्न हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन डा. मधु खन्ना और अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री श्रीरंग कुलकर्णी ने किया। अधिवेशन में शिक्षा के व्यापारीकरण और देश की वर्तमान स्थिति पर दो प्रस्ताव पारित किया गया।

अधिवेशन के अगले दिन अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी। शोभा यात्रा अनारदाना चौक पर आयोजित खुले अधिवेशन स्थल पर पहुंची। जहां विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने शिक्षा के व्यापारीकरण, कश्मीर में अलगाववाद की समस्या और आतंकवाद मुद्दे पर भाषण दिया।

अधिवेशन के आखिरी सत्र में प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर नयी कार्यकारिणी की घोषणा की गयी। विपन प्रधान को प्रांत अध्यक्ष और प्रांत मंत्री के रूप में आशुतोष तिवाड़ी के नाम की घोषणा की गयी। समापन समारोह में अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री बलविन्दर सिंह ठाकुर ने अधिवेशन में आये प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

अलगावाद का जहर

● मिथिलेश झा

अपने चिरपरिचित स्वर में भारत के खिलाफ जहर उगलने, आजादी को अपना पैदाइशी हक बताने और कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की हिमायत करने वाले हुर्रियत के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी नई दिल्ली में जूतेबाजी का शिकार हो गए। 'कमेटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटकल प्रिजनर' द्वारा आयोजित 'आजादी-एकमात्र रास्ता' नामक सम्मेलन में शिरकत करने आए गिलानी के अनुसार कश्मीर घाटी ही नहीं, बल्कि जम्मू व लद्दाख भी हिंदुस्तान के कब्जे से आजाद होने चाहिए।

सत्ता की नाक के नीचे राष्ट्रद्रोह की ऐसी बात जहां पूरे देश के लिए चौंकाने वाली हैं वहीं कांग्रेस के लिए शर्म की भी। जम्मू-कश्मीर की आजादी की बात कहकर गिलानी ने देश की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता पर ही प्रहार किया है। दूसरी ओर, कश्मीर समस्या सुलझाने में भारत, पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर की त्रिपक्षीय वार्ता की बात कह गिलानी कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी विलय को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। वह भी ऐसे समय जब घाटी में पृथकतावादी तत्वों ने पुन: अपना तांडव शुरू कर दिया है। दरअसल कश्मीर मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने का सारा तामझाम अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के भारत आने से पहले किया गया, लेकिन अमेरिका ने बयान देकर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है।

गिलानी ने आत्म-निर्णय के अधिकार को कश्मीरियों के लिए मूल अधिकार बता कर परोक्ष रूप से भारतीय संविधान की आत्मा को ही नष्ट करने का प्रयास किया है। गिलानी के अतिरिक्त लेखिका अरुंधती राय ने भी इस सम्मेलन में अलगाववाद के पक्ष में अपने कुतर्क पेश किए। अलगाववादी आंदोलन को जनआंदोलन बताते हुए अरुंधती राय ने कहा कि कश्मीर को बार-बार भारत का अभिन्न अंग बताया जाता है, जबकि यह कभी अभिन्न अंग रहा ही नहीं।

इन्हें यह बात समझनी होगी अथवा समझानी होगी कि कश्मीर का मन भारत के साथ जीता है। भारत में कश्मीर का विलय अब कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि समय ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। भारत को उपनिवेशवादी और खोखली महाशक्ति बताते हुए तथाकथित बुद्धिजीवी लेखिका ने आदिवासियों के हाथों में धनुष-बाण और कश्मीरी युवकों के हाथों में पत्थर होना जरूरी ही नहीं, बल्कि इसमें अभी और वृद्धि होने की बात कहीं। ऐसा बयान उनकी भारतीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए उन्हें सोचना चाहिए कि इससे उत्तर-पूर्व राज्यों के अलगाववादियों में गलत संदेश जाएगा।

नि:संदेह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के संचालन का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन इस आधार पर देश तोड़ने की बात कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) प्रत्येक नागरिक को भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में शामिल आठ प्रमुख उपबंधों-राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए प्रोत्साहन के अतिरिक्त देश की संप्रभुता तथा अखंडता के हितों में या आधारों पर इस अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त सीमाएं अथवा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

इस आधार पर केन्द्र सरकार की दो प्रमुख जिम्मेदारी बनती हैं। एक यह कि गिलानी, अरुंधती और सम्मेलन में शामिल उन सभी वक्ताओं पर, जिन्होंने अलगाववाद के पक्ष में अपने कुतर्क दिए, राष्ट्रद्रोह के मामले में कठोर कार्रवाई करे और दूसरी यह कि ऐसे राष्ट्रविरोधी और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि फिर ऐसा दुस्साहस कोई अन्य न कर सके।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

श्रद्धाञ्जलि

महान वैज्ञानिक डॉ. जगदीश चन्द्र बसु

'उठो, मन की मलीनता हटाओ।' सुविधायें नहीं है, प्रयोगशालायें नहीं हैं, कह कर बैठने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा मन ही सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। आलस्य त्यागो, जहां हो वहीं से कार्य आरम्भ करो। 'याद रखो, जो लोग वित्तेषणा व लोकेषणा के लिए कार्य नहीं करते, असफलतायें उन्हें रोक नहीं पातीं।

-डॉ. जगदीश चन्द्र बसु'

वैदिक काल से ही भारत में विज्ञान के कई क्षेत्र विकसित थे। भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र, कृषि, गणित, नक्षत्रविज्ञान, जीवविज्ञान, आयुर्वेद, धातुविज्ञान और विभिन्न कला-कौशल भी अध्ययन व प्रयोग का क्षेत्र था। देश में सर्वसाधारण लोगों में यह धारणा प्रचलित है कि विज्ञान पश्चिम की देन है। परन्तु 20वीं सदी के प्रारंभ में जगदीशचन्द्र बसु ने अपने गहन अध्ययन के द्वारा सिद्ध किया कि भारत मात्र धर्म दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं अपितु विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में भी अग्रणी था।

जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवम्बर, 1858 में ढाका जिले के फरीदपुर के माइमसिंह गांव में हुआ था, जो कि अब बंग्लादेश का हिस्सा है। ग्यारह वर्ष की आयु तक इन्होंने गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। बाद में ये कलकत्ता आ गये और सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। भौतिकशास्त्र में बी.ए. की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् 22 वर्षीय बसु चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए मगर स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से इन्होंने चिकित्सक बनने का विचार त्याग कर कैम्ब्रिज के क्राइस्ट महाविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान विषय में प्रवेश लिया।

वर्ष 1885 में ये स्वदेश लौटे तथा भौतिकी के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। यहां वह 1915 तक रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में एक तिहाई वेतन दिया जाता था। इसका जगदीश चंद्र बसु ने विरोध किया और बिना वेतन के तीन वर्षों तक काम करते रहे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति आर्थिक खराब हो गई और उन पर काफी कर्जा हो गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़ी। चौथे वर्ष जगदीश चंद्र बसु की जीत हुई और उन्हें पूरा वेतन दिया गया। वे एक अच्छे शिक्षक भी थे, जो कक्षा में पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का उपयोग करते थे। बसु के ही कुछ छात्र जैसे सत्येन्द्र नाथ बोस आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री बने।

इसी दौरान जगदीश चंद्र बसु ने सूक्ष्म तरंगों (माइक्रोवेव) के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य तथा अपवर्तन, विवर्तन एवं ध्रुवीकरण के क्षेत्र में अपने प्रयोग भी प्रारंभ कर दिये थे। लघु तरंगदैर्ध्य, रेडियो तरंगों तथा श्वेत एवं पराबैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गैलेना क्रिस्टल का प्रयोग बसु के द्वारा ही विकसित किया गया था। मारकोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बसु ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बसु ने दूर से एक घंटी बजाई और बारूद में विस्फोट कराया था। इसके बाद बोस ने किसी घटना पर पौधों की प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। बसु ने दिखाया कि यांत्रिक,

ताप, विद्युत तथा रासायनिक जैसी विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं में सब्जियों के ऊतक भी प्राणियों के समान विद्युतीय संकेत उत्पन्न करते हैं।

जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि चेतना केवल मनुष्यों और पशुओं तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह वृक्षों और जिन्हें निर्जीव पदार्थ माना जाता है, उनके अंदर भी समाहित है। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक जगत के सामने जीवन के एकत्व को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि निर्जीव व सजीव दोनों निरपेक्ष नहीं, अपितु सापेक्ष हैं। उनमें अंतर केवल इतना ही है कि धातुएं थोड़ी कम संवेदनशील होती हैं, वृक्ष कुछ अधिक संवेदनशील होते हैं, पशु कुछ और अधिक तथा मनुष्य सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। इनमें डिग्री का अंतर है, परन्तु चेतना सभी के अंदर है। अपने प्रयोग को कई बार दोहराकर उन्होंने जांचा-परखा तथा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि निर्जीव के अंदर भी संवेदनशीलता है।

जगदीश चंद्र बसु ने जब यह सिद्ध किया, उस समय पश्चिम के वैज्ञानिकों की क्या हालत थी, इसका अनुभव निम्न प्रसंग से किया जा सकता है। रायल साईंटिफिक सोसायटी में जगदीश चन्द्र बसु का भाषण होने वाला था तो इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध बायोलाजिस्ट हारटांग को हॉब्ज नामक विद्वान ने कहा-आज जगदीश चंद्र बसु का भाषण होने वाला है जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि वनस्पतियों और निर्जीवों में भी जीवन रहता है। आप भाषण सुनने चलेंगे? हारटांग की प्रथम प्रतिक्रिया थी 'मैं अभी होश में हूं, मैंने पी नहीं रखी है। आपने कैसे समझ लिया कि मैं ऐसी वाहियात बातों पर विश्वास करूंगा।' फिर भी मजा देखने की मानसिकता से वे भाषण सुनने आए। और भी लोग हंसी उड़ाने की मानसिकता से वहां आए। जगदीश चंद्र बसु ने केवल मौखिक भाषण ही नहीं दिया अपितु यंत्रों के सहारे प्रत्यक्ष प्रयोगों का प्रदर्शन करते हुए जब अपनी बात सिद्ध करना प्रारंभ किया, तो हाल में बैठे सभी विद्वान जो प्रारंभ में उपेक्षा की नजर से देख रहे थे, 15 मिनट बीतते-बीतते तालियां बजाने लगे। सारा हाल उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

भाषण व प्रयोगों के अंत में जब सभा के अध्यक्ष ने पूछा कि किसी को कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो वक्ता से पूछ सकते हैं। तीन बार दोहराने पर भी जब कोई नहीं बोला, तब प्रो. हॉब्ज खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कुछ भी पूछने लायक नहीं है। बसु महोदय ने अत्यन्त प्रामाणिकता से अपनी बात सिद्ध की है। उनके भाषण व प्रयोगों को देखकर मन में शंका उठती थी, परंतु अगले ही क्षण दूसरे प्रयोग को देखकर उस शंका का निरसन हो जाता था। रायल सोसायटी के अध्यक्ष ने भी जगदीश चंद्र बसु के जीवन के एकीकरण को सिद्ध करने की दिशा के सफल प्रयत्न के प्रति विश्वास प्रकट किया।

आगे चलकर बसु महोदय ने वृक्षों के ऊपर बहुत गहराई से प्रयाग किए। अपने साथ पौधों को लेकर दुनिया की यात्रा की। अनेक संवेदनशील यंत्र बनाये जिनमें वृक्षों के अंदर होने वाले सूक्ष्मतम परिवर्तन प्रत्यक्ष देखे जा सकते थे। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया, जो संवेदनाओं को एक करोड़ गुना अधिक बड़ा कर बताता था। जब पौधों को वे यत्र लगा दिए जाते थे, तो पौधे दिन भर में क्या-क्या अनुभूतियां उन्हें हो रही हैं, इसकी कहानी मानों स्वयं कहने लगते थे।

1917 में जगदीश चंद्र बसु को 'नाइट' (Knight) की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रायल सोसायटी लंदन के फैलो चुन लिए गए। बसु ने अपना पूरा शोधकार्य बिना किसी अच्छे (महंगे) उपकरण और प्रयोगशाला के किया था इसलिए जगदीश चंद्र बसु एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। 'बोस इंस्टीट्यूट' (बोस विज्ञान मंदिर) इसी सोच का परिणाम है जो कि विज्ञान में शोधकार्य के लिए देश का एक प्रसिद्ध केन्द्र है। बसु का निधन 23 नवम्बर 1937 को गिरिडीह, बिहार में हुआ। जगदीश बसु की जीवन-गाथा ऐसे सभी नौजवान भारतीयों द्वारा गहरे और प्रबल विचार के योग्य है जिनका उद्देश्य विज्ञान की सेवा या विवेक या सामाजिक भावना के अन्य उच्च कार्य के लिए अपने आपको तैयार करना है।

(संकलनकर्ता : अवनीश सिंह)

महंगी शिक्षा के विरोध में विद्यार्थी परिषद् का हस्ताक्षर अभियान

लखनऊ। शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने आन्दोलन को तेज करते हुए सड़क पर आने की तैयारी कर ली है। अभाविप के सदस्यों ने राजधानी सहित प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में महंगी शिक्षा और व्यापारीकरण के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया है।

हस्ताक्षर अभियान लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एक साथ शुरू किया है।

शिक्षा के बाजारीकरण के मुद्दे पर आने वाले दिनों में बड़े आन्दोलन की तैयारी की जा रही है। ■

मिर्जापुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से केबीपीजी कालेज गेट के सामने बैनर पर हस्ताक्षर कराकर शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की गई। परिषद् के पदाधिकारियों ने शिक्षा क्षेत्र को व्यापार का रूप दिए जाने का विरोध जताया।

हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान परिषद् के विभाग संयोजक धनंजय त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैल गया है। शिक्षा के व्यापारीकरण के कारण पूरे प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जिला संयोजक राम सेवक बिंद ने कहा कि भारत कभी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु था, आज जबकि गरीब छात्र शिक्षा पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ■

लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति का पुतला दहन

अभाविप ने लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बीएड विद्यार्थियों के साथ किये गए छलावे के विरोध में कुलपति प्रो. मनोज कुमार मिश्र का पुतला फूंककर विरोध जताया। ।

अभाविप ने आरोप लगाया कि लविवि प्रशासन की गलती से कई कालेजों में सीटों से अधिक प्रवेश हो गए हैं। अतिरिक्त प्रवेशों के विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में समायोजित करने के नाम पर उनकी काउंसिलिंग करायी जा रही है। लविवि प्रशासन ने गलती की और अब खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि तीसरी काउंसिलिंग के लिए बचाकर रखे गए कालेजों के विकल्प भी खोले जाएं।

अभाविप ने पूरे प्रकरण में कुलपति द्वारा साधी गई चुप्पी पर असंतोष जताया है। परिषद ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नितिन मित्तल, अनुभव तिवारी, आशुतोष मिश्र समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश भर से आए सैकड़ों भुक्त भोगी छात्र-छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया।

■

लोग चाहे मुट्ठी भर हों, लेकिन संकल्पवान हों, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं।

-महात्मा गाँधी

अभाविप का आंदोलन रंग लाया

पूर्व कुलपति कमलाकर सिंह की पीएचडी की डिग्री निरस्त

भोज विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कमलाकर सिंह की पीएचडी की डिग्री निरस्त कर दी गयी। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए बहुमत के आधार पर यह निर्णय लिया है। श्री सिंह पर चोरी की सामग्री के आधार पर पीएचडी की डिग्री हासिल करने का आरोप सिद्ध होने पर यह कार्रवाई की गई है। विदित हो कि श्री सिंह ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से 1987 में डा. एस.पी. नार्टन के निर्देशन में जंतु विज्ञान विषय में पीएचडी की थी। उस समय श्री सिंह विश्वविद्यालय में सहायक कुलपति के पद पर कार्यरत थे। उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए कार्यपरिषद ने पाया कि श्री सिंह ने पेज संख्या पांच से 35 तक अपने गाइड श्री नार्टन के थीसिस से हू-ब-हू नकल की है।

अभाविप द्वारा भोज वि.वि. में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी तत्कालीन कुलपति कमलाकर सिंह के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया गया। इन्हीं संघर्षों के परिणामस्वरूप कमलाकर सिंह को कुलपति के पद से हटाया गया था। अभाविप ने इस मामले में 2004 में न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका भी दायर की थी।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णु दत्त ने कहा कि कार्य परिषद के इस निर्णय से शिक्षा में भ्रष्टाचार करने वालों को अच्छा सबक मिलेगा। साथ ही सम्पूर्ण शैक्षिक जगत ऐसे निर्णयों से लाभान्वित होकर विकास की ओर अग्रसर होगा। अभाविप ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए यह मांग की है कि कमलाकर सिंह पर चल रहे धारा 420 के प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफतार किया जाये। साथ ही इस पीएचडी के आधार पर उन्होंने जितने भी वित्तीय लाभ लिये है उनकी वसूली की जानी चाहिये। ■

अगले सत्र से होंगे छात्र-संघ के प्रत्यक्ष चुनाव

मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अगले सत्र से प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराये जायेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के.के. लोहाटी और न्यायाधीश सुषमा श्रीवास्तव की दो सदस्यीय खंडपीड ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री अश्विनी परांजपे की याचिका पर सुनवायी करते हुए यह निर्णय सुनाया है।

अभाविप द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि लिंगदोह समिति की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ का गठन नहीं कराया जा रहा है। इससे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने अगले सत्र से लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही है।

अभाविप ने इसे लंबे समय से किये जा रहे आंदोलनों और संघर्षों की जीत बताया है। परिषद का मानना है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ के गठन से छात्रों की नेतृत्व प्रतिभा को निखरने का मौका मिलेगा। ■

'फार्मा विजन-2020' का आयोजन

'इंडियन फार्मासिस्ट: ए होप फार हेल्दी नेशन' की घोषणा के साथ 'फार्मा विजन 2020' विषय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुजरात प्रांत द्वारा दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

सितम्बर 18-19 को हुए इस सेमिनार का उद्घाटन गुजरात टेक्नोलाजिकल विश्व विद्यालय अहमदाबाद के कुलपति डा. अक्षय अग्रवाल ने किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डा. अग्रवाल ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। अब हम सभी लोगों को मिलकर उसी शैक्षिक स्तर को प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध होने की आवश्यकता है।

उन्होंने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सर्वांगीण विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिये केवल वर्गस्तरीय शिक्षण पर्याप्त नहीं है इसके लिये हमें फार्मा विजन 2020 जैसे रचनात्मक और संवाद आधारित कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में उपस्थित श्री देवांगभाई ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ फार्मासिस्टों का निर्माण करना ही नहीं अपितु इस तरह के रचनात्मक कार्यों के माध्यम से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा छात्र संगठन है जो आन्दोलनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों द्वारा युवाओं में सर्वांगीण विकास के साथ देश से जोड़ने का कार्य करता है।

उद्घाटन कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री श्री के.एन. रघुनंदन ने विदेशी और महंगी दवाओं के विकल्प में देश में निर्मित कम कीमतों वाली दवाओं के निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिये कि अपने देश में ऐसी किस्मों को बनाने पर जोर देना चाहिये जो गरीब और पिछड़े लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। सेमिनार में फार्मान्जा हर्बल प्रा.लि. के जनरन मैनेजर डा. प्रतीक पटेल ने कहा कि हमें भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधियों को देशवासियों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये।

बस्तर में फूंका कुलसचिव का पुतला

दंतेवाड़ा-बस्तर विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितता व पूरक परीक्षा के प्रश्नपत्रों में लगातार त्रुटियों से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फरसपाल चौक पर कुलसचिव का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

अभाविप का कहना है कि जिला मुख्यालय स्थित एकमात्र पीजी कालेज में साइंस के टीचर की नियुक्ति न होने से परेशान छात्र कालेज छोड़ने को मजबूर हैं। अभाविप ने वि.वि. प्रशासन पर आरोप लगाया कि बस्तर विश्वविद्यालय में चल रहे पूरक परीक्षा में लगभग सभी कक्षाओं के प्रश्नपत्र में त्रुटि देखने को मिल रही है। प्रदर्शन के दौरान नगर मंत्री गणेश यादव, आशीष कुमेटी, गुजराल शार्दूल, पीलेश्वर सेठिया आदि मौजूद थे। ■

पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान के द्वारा ही हम इंद्रियों पर संयम रख सकते हैं। मन को रोकना, इन्द्रियों को रोकने का बल, कष्ट सहने की शक्ति और चित्त की शुद्धि तथा एकाग्रता को बनाए रखने में ध्यान बहुत सहायक होता है।

-स्वामी विवेकानन्द

व्यापारीकरण के विरोध में पोस्टर व स्टीकर का विमोचन

डुंगरपुर (राजस्थान)। अभाविप की डुंगरपुर जिला इकाई ने परिषद कार्यालय पर कार्यक्रम कर शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में विद्यार्थी परिषद के प्रफुल्ल आकोत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विवेक रावत, जिला संयोजक जितेन्द्र बरंडा सहित कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने पोस्टर व स्टीकर का विमोचन किया।■

उत्तराखण्ड : रूड़की IIT में लिपिस्टिक प्रतियोगिता का विरोध

रूड़की। इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूड़की के वार्षिकोत्सव के दौरान विवादास्पद लिपिस्टिक प्रतियोगिता की आलोचना करते हुए अभाविप ने आईआईटी प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही साथ परिषद ने इस प्रकरण की जांच की मांग की है।

इस गैर-सांस्कृतिक कृत्य के विरोध में इंजीनियरिंग संस्थान के परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने संस्थान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका।

राज्य सरकार ने इस मसले पर उपजे विरोध को देखते हुए जांच बिठा दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि ऐसी किसी भी अभद्र गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन द्वारा इस संबंध में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है।

■

56वें राष्ट्रीय अधिवेशन का बेंगलुरु में आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 56वां राष्ट्रीय अधिवेशन कर्नाटक की राजधानी बेंगालुरु में आयोजित किया जा रहा है। 25 से 28 दिसम्बर तक चलने वाले इस चार दिवसीय अधिवेशन की तैयारी जोरों पर हैं। इस अधिवेशन में देश के विभिन्न स्थानों से लगभग आठ हजार प्रतिनिधि भाग लेंगे।

इस अधिवेशन में केन्द्र और राज्य सरकारों की शिक्षा नीति की समीक्षा, वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा का व्यापारीकरण और छात्र हितों से जुड़े अन्य कई विषयों पर चर्चाएं इस अधिवेशन का मुख्य विषय रहेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था का स्तर, मूल्य-वृद्धि, भ्रष्टाचार और अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल रहेंगे। ■

जिस बहुमुखी दासता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसके लिये आत्मा के अन्दर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिये, जिससे सत् और असत् का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है।

-लोकमान्य बालगंगाधर तिलक

शिक्षा मंत्री को खुला पत्र

'केन्द्र सरकार शिक्षा-नीति स्पष्ट करे'

महोदय,

राष्ट्रीय विकास की सही दिशा के साथ जोड़ने के लिए वर्तमान शैक्षणिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता लम्बे समय से अनुभव होने के बाद भी आज देश में यह आम सहमति है कि इस दृष्टि से अभी तक सार्थक और ठोस कदमों का बुरी तरह अभाव रहा है। यद्यपि शैक्षिक ढांचे का काफी विस्तार हुआ है और समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रयोग भी हुए हैं, लेकिन ये प्रयास या तो अधूरे रहे हैं या गलत दिशा में रहे हैं। यह एक कटु सत्य है कि स्वामी विवेकानन्द, श्री अरविन्द, श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर, महामना मालवीय और महात्मा गांधी द्वारा इस विषय पर दिखाये गये रास्ते से हम भटक गये हैं। इसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि एक ओर राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रों में मूल्य-निष्ठा का जबरदस्त अभाव है एवं भ्रष्टाचार-उच्छृंखलता-अनुशासनहीनता का वातावरण फैला हुआ है तथा दूसरी ओर समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा के लाभ से अछूता है, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सम्पन्न और गरीब लोगों के लिए मौजूद दोहरा ढांचा विषमता की खाई को गहरा बना रहा है, बेरोजगारी की समस्या निरन्तर भीषण रूप धारण कर रही है। हमें विश्वास है कि उपरोक्त संदर्भ में आप भी बहुत चिन्तित होंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मुद्दे पर पिछले वर्षों में देश का ध्यान आकृष्ट करने का लगातार प्रयास किया है। 9 अगस्त, 1978 को केन्द्र सरकार को दिये गये ज्ञापन में हमने शैक्षिक परिवर्तन के लिए ठोस सुझाव रखे थे तथा इस दिशा में कार्यान्वयन पर जोर देने के लिए गत 6 मार्च 1979 को देश के लगभग 8 लाख छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के हस्ताक्षर से युक्त एक याचिका संसद को प्रस्तुत की थी। इसी संदर्भ में हम इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं कि केन्द्र सरकार शिक्षा-नीति पर स्थिति स्पष्ट करे। केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि :

(1) राष्ट्रीय विकास योजना में शैक्षिक परिवर्तन को उचित प्राथमिकता दी जाये तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों ही स्तरों पर सुसंगठित एवं समन्वित प्रयास किये जायें। शैक्षिक सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय का न्यूनतम 10 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो।

(2) शैक्षिक प्रशासन को सभी स्तरों पर स्वच्छ एवं सक्षम बनाने के साथ ही स्वायत्त, विकेन्द्रित एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए युक्तिसंगत ढांचा विकसित किया जाये। राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्धारण और इसके कार्यान्वयन में समन्वय एवं समीक्षा के लिए सर्वोच्च अधिकार एवं संवैधानिक-स्वायत्तता प्राप्त 'राष्ट्रीय शिक्षापीठ' (नेशनल एजुकेशन फाउन्डेशन) की स्थापना की जाये। केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपनी नीति तय करें लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का निर्धारण एवं संचालन ऐसी स्वायत्त संस्था द्वारा किया जाये जो दलीय-राजनीति के प्रभावों से मुक्त हो।

(3) भारतीय जीवन-मूल्यों एवं आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए शिक्षा की विषय वस्तु में व्यापक बदल हो। भारतीय संस्कृति की सम्पन्न विरासत और राष्ट्रीय एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टि के इतिहास के शिक्षण पर बल देकर शिक्षा को भारतीय जीवन-मूल्यों से जोड़ा जा सकता है। शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए सुनियोजित प्रयास किया जाये। बेरोजगारी की समस्या का सामना करने तथा शिक्षा के रोजगारोन्मुखीकरण को सार्थक एवं प्रभावी बनाने के लिए आर्थिक-औद्योगिक तंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जाये ताकि लघु एवं कुटीर उद्योगों को कानूनी संरक्षण एवं हर सम्भव प्रोत्साहन मिल सके तथा इनके द्वारा सम्भव उत्पादन को बड़े उद्योगों एवं मल्टीनेशनल कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता से बचाया जा सके। राष्ट्रीय विकास योजना एवं शिक्षा को ग्रामोन्मुखी बनाने के लिए ठोस कार्यवाही की जाये।

(4) सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाये।

(5) शिक्षा के अवसरों में समानता के लिए प्रयास हो ताकि सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शिक्षा का समुचित लाभ मिल सके। पब्लिक-स्कूलों का वर्तमान ढांचा समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

(6) शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता एवं अस्तव्यस्तता को समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।

हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि उपरोक्त मुद्दों पर समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए उचित स्तर पर शीघ्र निर्णय लिया जाये।

हमें आशा है कि आप इस दिशा में समुचित कदम यथाशीघ्र उठायेंगे और हमें निराश नहीं करेंगे। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के हर कार्य में यथासम्भव सहयोग के लिए हम सदैव तैयार हैं।

(**महेश शर्मा**, महामंत्री, अ.भा.वि.प.)

अप्रैल 1980 राष्ट्रीय छात्रशक्ति के अंक से लिए अंश

देश में सुशासन की नयी परिभाषा

मध्यप्रदेश का लोक सेवा प्रदान की गारंटी का कानून

|| प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्
नात्मप्रियं हित राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ||

(अपने नागरिकों की खुशी में ही उसकी खुशी है, लोगों के कल्याण में ही उसका कल्याण। जो कुछ भी उसे संतुष्ट करता है उसे वह अच्छा नहीं मानेगा लेकिन जो कुछ उसके लोगों को संतुष्ट करे, उसे ही वह श्रेष्ठ मानेगा।)

(कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में कल्याणकारी राज्य की धारणा)

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

- राज्य की विधानसभा ने इसी मानसून सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010. जनाधिकार को मान्यता देते हुये सुराज के पथ पर देश के किसी राज्य में पहली बार उठा यह अभिनव कदम।
- लोक प्रशासन में प्रारंभिक रूप से चिंहित 25 सेवाओं जैसे आय, जाति, स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र, खसरे-खतौनी की नकल, राशन कार्ड, बिजली और नल के नए कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और इसी प्रकार की अन्य सेवाओं की समय सीमा की जवाबदेही।
- सेवा प्रदान करने में चूक या देरी करने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान। अपील मान्य होने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना। जुर्माने की राशि संबंधित नागरिक को।
- सुराज की धारणा को नई ऊंचाई देने वाले इस कानून को लागू करने के लिये नये लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन।

जनाधिकार में जनता के साथ, ***मध्यप्रदेश सरकार***

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आर.एन.आई. न. 32464/78

भोपाल की विशाल छात्र रैली का एक विहंगम दृश्य

दीपावली मिलन कार्यक्रम - बेंगलुरु

दीपावली मिलन दिल्ली के कार्यक्रम में विदेशी छात्रों के साथ (बाये से) **WOSY** उपाध्यक्ष श्री संदीप महापात्रा व **WOSY** अध्यक्षा डॉ. रश्मि सिंह

WOSY के दीपावली मिलन कार्यक्रम बेंगलुरु में दीपोत्सव मनाते हुए छात्र एवं हैदराबाद में नृत्य प्रस्तुती